

रजिस्टर नं ० HP/13/SML-2005.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 14 जूलाई, 2005/23 अष्टावृ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

प्रधिसूचना

शिमला-२, 14 जूलाई, 2005

मंडया एल० एस० आर०-डी०(6)-22/2005-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के मंविधान के घनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12-7-2005 को प्रकाशित

हिमाचल प्रदेश मूल्यपरिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्याक 8) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत अप्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

ग्राहण द्वारा,

हस्ताधारित/-
सचिव (विधि) ।

2005 का हिमाचल प्रवेश अध्यादेश संख्यांक 8.

हिमाचल प्रवेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005

भारत गणराज्य के उपनिवेश वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राजपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राजपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कारंबाइ करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राजपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के बाण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अध्यादेश, 2005 है।

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62 की उप-धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तु जोड़े जाएंगे, अर्थात् :- धारा 62 का संशोधन।

“परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसचना द्वारा किसी भी डॉग्हारी को, जाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् रजिस्ट्रीकूट हो, अधिनियम के अधीन विनियमित माल के विक्रय पर उद्घरणीय कर की किसी भी प्रकार की रियायत का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेंगी, यदि ऐसी रियायत की घोषणा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार अधिसचना द्वारा, पर्वतीं परन्तुके अधीन कर से लौट की रियायत के बदले में, कैरिल कर के आस्थगित संदाय की प्रसुविधा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात कर सकेंगी जैसी यह उसमें विनिर्दिष्ट करे।”।

विष्णु सदाशिव कोक्जे,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

गिमला :

तारीख....., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 8 of 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2005**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005.

Amendment of section 62.

2. In section 62 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after sub-section (5), the following provisos shall be added, namely :—

“Provided that the State Government may, by notification, allow any dealer, whether registered before or after the commencement of this Act to avail of any incentive of tax leviable on the sale of manufactured goods under the Act, if such incentive has been declared by the State Government before the commencement of this Act :

Provided further that the State Government may by notification, in lieu of the incentive of exemption from tax under the preceding proviso, allow only the facility of making deferred payment of tax, subject to such conditions as it may specify therein.